समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युवा पीढ़ी को करें तैयारः पटेल

युवाओं के कौशल विकास और स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ ही विश्वविद्यालयों को बनाएंगे आत्मनिर्भरः डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि बाबा साहेब ने अपनी अद्भुत दूरदृष्टि से हमें संविधान के रूप में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, धन और शक्ति बल आदि के भेदभावों से मुक्त समावेशी, समरस समाज की धरोहर सौंपी है। राज्यपाल शुक्रवार को महू में डॉ. बीआर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलाधिपति डॉ. प्रकाश सी बरततूनिया, विधायक सुश्री उषा ठाकुर उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि हमारा संविधान प्रेरणादायक जीवंत दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है, जिसका समर्पित भाव से पालन, हर भारतीय का परम कर्तव्य है। विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान का अपने आचरण, व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। समाज के तुलनात्मक रूप से वंचित, पिछड़े वर्गों, समुदायों के भाई बहनों के विकास की जवाबदारी, जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के सपनों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षण संस्थानों को ऐसे नागरिकों को तैयार करने का अवसर दिया है। यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय

और शिक्षक, हमारी संस्कृति के अनुरूप देश और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक समृद्धि और समानता के प्रति समर्पित युवा ध्वज वाहक तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने को गौरव की बात बताते हुए अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो सीखा, वो समाज को समर्पित किया। देश का संविधान इस बात का प्रमाण है जिसमें भारत की विविधता भरी संस्कृति, जनजाति नागरिक आदि को एक साथ जोड़ा गया है। बाबा साहेब ने चित्रों के संयोजन से संविधान को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रहने के दौरान इस विश्वविद्यालय में कई संकाय शुरू किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक और नए संकाय खोले जाएँगे। जनवरी माह में राज्यपाल की अध्यक्षता में कुलगुरूओं की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाने का मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास और स्पष्ट दिशा देने के साथ ही विश्वविद्यालय की आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए जाएँगे। दीक्षांत समारोह में संस्थान के 16 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। विवि द्वारा विगत 5 वर्षों में 100 से अधिक शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वहीं बीते सत्र में विश्वविद्यालय से 851 विद्यार्थियों ने डिग्री हासिल की है। इसमें से पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर डिग्री प्रदान की गई। आरंभ में अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती, भगवान बुद्ध और बाबासाहेब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन विश्वविद्यालय के कुलगुरु रामलाल अत्राम ने दिया। आभार कुल सचिव ने माना।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलने में सक्षमः मुख्यमंत्री

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश की विश्व में विशिष्ट छवि बनाने में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भारत की अलग पहचान बनी है और देश को आदर-सम्मान के साथ देखा जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा का स्वरूप अन्य सेवाओं से भिन्न है। कठोर परिश्रम के साथ-साथ ईश्वर प्रदत्त भाग्य से ही मनुष्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा से जन सेवा का अवसर प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मीट-2024 का प्रशासन अकादमी में शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री का अंगवस्त्रम् भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने डॉ. यादव को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने पौराणिक संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि ईश्वर प्रदत्त यश का सदुपयोग जनहित में करना ही श्रेष्ठतम है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलने में सक्षम हैं। व्यक्तिगत स्तर पर की गई ऐसी पहल, सुख और संतोष प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार बेहतर अवसरों के साथ अपनी दक्षता और सूझ-बूझ से लिए गए निर्णय और उनके बेहतर क्रियान्वयन से ही अधिकारी इतिहास बनाते हैं।

डॉ. यादव ने कहा कि व्यवस्था संचालन में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग-अलग दायित्व हैं। उनके निर्वहन की अपनी-अपनी विशेषज्ञता भी है। इन सभी संस्थाओं ने लोकतंत्र को बनाए रखने में अपने-अपने स्तर पर योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेना या एक विचार देना सरल है, लेकिन बड़े फलक पर उसका क्रियान्वयन चुनौती पूर्ण होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की निर्णयों के क्रियान्वयन में दक्षता प्रशंसनीय है।

सेवाकाल के बाद भी देश की उन्नति और जनकल्याण में दें योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सर्विस मीट का विचार मंथन नए दौर के नए मध्यप्रदेश के निर्माण में सहायक होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के लंबे अनुभवों को साझा करने के लिए किसी संस्था की संरचना करने पर विचार होना चाहिए। इससे अलग-अलग क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ विचारों के आदान-प्रदान तथा सेवाकाल के बाद भी देश की उन्नति और जन कल्याण में अपना योगदान देने के लिए मंच उपलब्ध हो सकेगा। वैश्विक परिदृश्य में हो रही घटनाओं की दृष्टि से भारत का वर्तमान समय बहुत अनुकूल और सकारात्मक है। पड़ौसी देशों में हो रहे घटनाक्रम से इसका आंकलन किया जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की व्यवस्थाएं विश्व में आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं।

एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव से परिवार के मुखिया के रूप में सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तीन दिवसीय सर्विस मीट से एसोसिएशन के सदस्यों में टीम भावना विकसित करने, नवाचारों को जानने और सीखने तथा बेहतर परिणाम देने के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर प्राप्त होता है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन, जी-20 इंडिया के शेरपा तथा नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कांत, प्रशासन अकादमी के महानिदेशक जेएन कंसोटिया, एसोसिएशन के पदाधिकारी अनुपम राजन, विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।

विकास को दर्शाता है प्रदेश में म्यूचुअल फंड सेक्टर में सवा लाख करोड़ रुपए का निवेश

भोपाल(काप्र)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न सेक्टरों के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 68 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। प्रदेश में म्यूचुअल फंड में सवा लाख करोड़ रुपये का निवेश है, जो यहां हुए विकास को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के 2 दिवसीय निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार का बजट सवा तीन लाख करोड़ रुपये है जिसे बढ़ाकर 7 लाख करोड रुपये ले जाने के बड़े लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। हम अनावश्यक खर्चों को कम करके आय में वृद्धि करने पर जोर देते हुए कार्य कर रहे है। देश और प्रदेश हर क्षेत्र में बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। बदलते दौर में व्यवस्थाएं क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हुई है। उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में होने वाले मंथन के माध्यम से भविष्य के अच्छे सोपान निकल कर आएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक गोलू शुक्ला, गौरव रणदिवे, म्युचुअल फंड एसोसिएशन के सेंट्रल इंडिया अध्यक्ष राजेश कूलवाल, अभिलाष जैन, अमित माहेश्वरी, प्रमोद सराफ सहित देश भर के बड़ी संख्या में म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री आज उज्जैन आईटी पार्क का करेंगे भूमिपूजन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन आईटी पार्क का भूमिपूजन 21 दिसंबर को करेंगे। कार्यक्रम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदौर रोड में आयोजित होगा। इस अवसर पर कौशल विकास एवं रोजगार व उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उज्जैन आईटी पार्क लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। आईटी पार्क स्थापित होने से क्षेत्र में आईटी, आईटीएस, ईएसडीएम सेक्टर में निवेश के नए आयाम स्थापित होंगे और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। आईटी पार्क का विस्तार 2.16 हेक्टेयर भूमि पर होगा। पार्क की इमारत महाकाल की अनन्त की अवधारणा पर डिजाइन की जाएगी और 5 चरणों में इसका निर्माण होगा।

राष्ट्रीय बालरंग : भारत की विविध संस्कृति को जानने का मौका

भोपाल(काप्र)। राष्ट्रीय बाल रंग का प्रति वर्ष भोपाल में होना देशभर में मध्यप्रदेश को गौरवान्वित करता है। यह एक ऐसा मौका होता है, जब देश के विभिन्न प्रांतों के बच्चे अपने राज्यों की संस्कृति को समेटे प्रतिभा का प्रदर्शन भोपाल में करते हैं।

यह विचार शुक्रवार को निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय प्रो. अमिताभ पांडे ने बाल रंग के शुभारंभ समारोह में व्यक्त किये। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न संभागों से आये एक हजार से अधिक और विभिन्न प्रांतों के बच्चे मौजूद थे। प्रो. पांडे ने कहा कि प्रति वर्ष बाल रंग में बच्चों के आने से मानव संग्रहालय में रौनक आ जाती है। तीन दिवसीय समारोह में बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। प्रतियोगिता में बच्चों में टीम भावना भविष्य में उनको जिम्मेदार नागरिक बनाने में काफी मददगार साबित होती है। उन्होंने कहा कि देश की एकता विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों के सौहार्द मिलन से मजबूत होती है। संचालक लोक शिक्षण डीके कुशवाह ने बताया कि बाल रंग बच्चों में नयी ऊर्जा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि बाल रंग में लगने वाली प्रदर्शनी की थीम वर्ष 2047 में विकसित भारत रखी गयी है। स्वागत संबोधन में शिक्षा विभाग के अधिकारी अरविन्द कुमार चौरगड़े ने बताया कि पहले दिन प्रदेश के विभिन्न संभागों के बच्चे लोक संस्कृति पर आधारित नृत्यों और विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। बाल रंग में 21 और 22 दिसम्बर को 17 राज्यों सहित 5 केन्द्र शासित प्रदेश के करीब 10 हजार बच्चे सहभागिता करेंगे।

विविध गतिविधियां

बाल रंग में स्कॉउट कैम्प, विजन-2024 पर केन्द्रित सजीव प्रदर्शनी, विभिन्न राज्यों के व्यंजनों के स्टॉल लगाये गये हैं। बाल रंग की सबसे खास बात यह है कि यहां प्रदेश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति की दर्शाने के लिये राज्यों की स्टॉल लगाये गये हैं। इन स्टॉलों में उन राज्यों के पुरातत्व स्थल, लोक संस्कृति, त्यौहार, मंदिर, पारंपरिक वेश-भूषा देखने को मिलेगी। केरल राज्य के पंडाल में भोपाल के जवाहर चौक स्थित कस्तूरबा स्कूल की बालिकाओं ने मॉडल के जरिये वहां की संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर केरल का प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। प्राचार्य श्रीमती उषा भदौरिया और श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि केरल राज्य में ओणम का त्यौहार पारंपरिक रीति-रिवाजों और विशेष वेश-भूषा के साथ बनाया जाता है। बाल रंग में तात्कालिक भाषण, लोक गीत, शास्त्रीय नृत्य, सुगम संगीत, सामुहिक लोक नृत्य, दिव्यांगों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, वेद पाठ, नृत्य नाटिका, योग जैसी अनेक प्रतियोगिताएं होंगी।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की होगी जांच, आपराधिक प्रकरण होगा दर्ज

सीधी में आदिवासी की जमीन ओबीसी वर्ग को बेची

भोपाल(काप्र)। सीधी जिले में फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर आदिवासियों की जमीन खरीदने और बेचने का मामला राज्य विधानसभा में विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने उठाया है।

प्रश्नकाल में उनके सवाल का जवाब देते हुए जनजातीय मंत्री विजय शाह ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस मामले में चार बार संबंधित को बुलाया गया है लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में एक तरफा कार्रवाई का अधिकार भी जांच कराकर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल, विधायक टेकाम ने सदन में बताया कि सीधी जिले के मनीष कुंदेर एवं रजनीश कुंदेर ने फर्जी दस्तावेज के जरिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण बना लिए और आदिवासियों से जमीन खरीद ली। इसके बाद जब जमीन बेची तो खुद को ओबीसी बताकर बेच दी। ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तीन बार किया गया। पहले 1985 में प्रमाण पत्र बनवाया फिर 1988 में और इसके बाद 2002 में इस तरह के प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। इसके बाद मंत्री शाह ने जवाब देते हुए भरोसा दिलाया की जांच में सबकुछ सही पाया गया है तो आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराएंगे। विधायक चैन सिंह बरकड़े ने 89 आदिवासी ब्लॉक में खर्च हुए बजट की जानकारी मांगी तो मंत्री विजय शाह ने कहा- आप जानकारी दुरुस्त कर लें। अब 89 नहीं, 88 आदिवासी ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक कम हो गया है। ये सुनकर ओमकार मरकाम ने कहा- आपकी सरकार ने आदिवासियों का एक ब्लॉक कम कर दिया। इस पर शाह ने कहा- दिग्विजय सिंह सरकार में वो एक ब्लॉक कम किया गया था।

भूरिया ने हॉस्टल में मौत का मुद्दा उठाया

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा-सरकारी स्कूलों और आदिवासी छात्रावासों में सुरक्षा और संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धार के आदिवासी छात्रावास में दो छात्रों की मौत हुई थी। मामले में अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं। इस पर विजय शाह ने कहा- धार के मामले में दोषियों पर कार्रवाई हुई है। भूरिया ने उच्चस्तरीय समिति बनाकर छात्रावासों की जांच करने की मांग रखी। मंत्री शाह ने कहा- हम जांच दल बनाकर झाबुआ जिले में जांच कर लेंगे। इस पर विधायक भूरिया ने कहा- मुझे भी बतौर विधायक जांच दल में शामिल किया जाए। मंत्री ने कहा- आप विधायक हैं। हम सभी संभागों के लिए जांच दल बना रहे हैं। उसमें आप भी स्थानीय विधायक के तौर पर जा सकते हैं।

स्पेशल खबर *जलजीवन मिशन में गड़बड़ी पर उठे सवाल...*

जलजीवन मिशन की हकीकत सबको पता है : नागवंशी

भोपाल (काप्र)।

मप्र विधानसभा में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मामला उठा। पिपरिया से विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने कहा- जल जीवन मिशन की हकीकत सबको पता है। सरकार की मंशा हर गरीब को पानी देने की है।

ठेकेदारों की लापरवाही के कारण काम हुआ भी तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जो पाइप लाइन डाली गई है, उसे चालू करते हैं तो कहीं न कहीं से सीपेज हो जाती है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- यह मामला पिछले सत्र में भी उठा था। संसदीय कार्य मंत्री ने एक महीने में जांच करने का आश्वासन दिया था। 3 महीने हो गए। न जांच हुई, न सदन के पटल पर रिपोर्ट आई। जांच हुई है तो रिपोर्ट कब तक आएगी, वो बताएं। इस बीच पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इस मामले का निष्पक्ष रूप से ऑडिट कराया जाए कि वर्तमान में स्थिति क्या है? जब मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री था, उस समय जल निगम का गठन हुआ था। उसके बाद जल जीवन मिशन आया। उसी के अंतर्गत यह काम हो रहा है। पाइप लाइन डालने के लिए सडक़ें खोद दी गईं। अलग-अलग योजनाओं से महंगी और अच्छी सडक़ें बनाई गई थीं। सबको तोड़ दिया गया। मेरा सुझाव है कि सदन के सदस्यों की समिति बनाकर देखें कि वास्तव में सरकार के पैसे का सदुपयोग हुआ है या नहीं। कई योजनाएं जो 2 साल में पूरी होनी थीं, 5 साल होने के बाद भी कंपलीट नहीं हुई।

249 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत टूटी हुई सडक़ों की जांच के लिए विधायकों की समिति बनाई जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले 249 ठेकेदारों को हमने ब्लैकलिस्ट किया है।

दो अशासकीय संकल्प मंजूर, केंद्र को भेजे जाएंगे

हरदा विधायक आरके दोगने ने जबलपुर व्हाया बुधनी हरदा रेलवे लाइन को देवास के संदलपुर तक जोडऩे का अशासकीय संकल्प रखा। इसे सर्वानुमति से स्वीकृत कर लिया गया। दूसरा संकल्प यादवेंद्र सिंह ने गुना अशोकनगर ललितपुर टीकमगढ़ बुडेरा छतरपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का रखा। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा- यह विषय सीधे तौर पर केंद्र सरकार का है। 2016 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। लेकिन सैद्धांतिक सहमति होना और स्वीकृत होने में फर्क है। 6 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखकर इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अनुरोध किया गया है। यादवेंद्र सिंह का अशासकीय संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत कर लिया गया। अब दोनों अशासकीय संकल्पों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।